भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2060

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में अमृत योजना का कार्यान्वयन

†2060. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत स्वीकृत और विकसित की गई जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, पार्कों और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित कर्नाटक में उक्त मिशन के तहत परियोजना-वार स्वीकृत, जारी, उपयोग की गई धनराशि और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और पूर्ण हुई, कार्यान्वयनाधीन तथा लंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है एवं यदि कोई देरी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कर्नाटक में, विशेष रूप से चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त मिशन के तहत लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने, समय पर धनराशि जारी करना सुनिश्चित करने और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार
द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) वर्ष 2015 में देश के चयनित 500 शहरों एवं कस्बों (वर्तमान में 15 विलयित शहरों सहित 485 शहरों) में प्रारंभ किया गया अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जलापूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र एवं पार्क आदि क्षेत्रों में बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित था। मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को मिशन दिशा-निर्देशों की व्यापक रूपरेखा के अनुरूप परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण तथा कार्यान्वयन का अधिकार प्रदान किया गया था।

अमृत पोर्टल पर कर्नाटक राज्य द्वारा अद्यतन की गई सूचना के अनुसार, अमृत के अंतर्गत राज्य में 5,112.54 करोड़ रु. की 404 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा चुका है, जिनमें से 5,061.97 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं। अनुमोदित परियोजनाओं में 2,213.09 करोड़ रु. की 44 जलापूर्ति परियोजनाएं, 2,499.92 करोड़ रु. की 55 सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 238.06 करोड़ रु. की 83 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं तथा 112.91 करोड़ रु. की 181 पार्क एवं हरित क्षेत्र परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में चित्रदुर्ग सहित शहर-वार परियोजनाओं की स्थिति वेबसाइट amrut.mohua.gov.in/approvedProjectsAmrut/ulb/OXhRK3hRdEZJSC9hdmxYZXVTM0ZFdz09 पर उपलब्ध है। चित्रदुर्ग शहर में अमृत के अंतर्गत राज्य द्वारा शुरू की गई सभी 15 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अमृत के तहत निधियाँ राज्यों को जारी की गई थीं, न कि शहर-वार या परियोजना-वार। अमृत के तहत, चित्रदुर्ग सहित अन्य परियोजनाओं के लिए राज्य को कुल 2258.85 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिसमें से राज्य ने 2238.78 करोड़ रुपये का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

मिशन दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) का प्रावधान है। इसके अलावा, मिशन के अंतर्गत गठित एक शीर्ष समिति आवधिक रूप से मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं की प्रगति एवं परियोजना-वार उपलब्धियों की निगरानी के लिए अमृत का एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है।

राज्य ने सूचित किया है कि परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, बाधाओं की पहचान तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विलंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त जनशक्ति, मशीनरी एवं तकनीकी संसाधन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

*****